



दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE



दैनिक भास्कर



जनसत्ता

Party

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

BY- ABHAY SIR

विश्व बांस दिवस

विश्व बांस दिवस: जानें इस बहुमुखी, पर्यावरण के अनुकूल संसाधन के उपयोग

दुनिया भर में बांस के पौधों की 1500 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस सूखे के प्रति बहुत सहनशील है और गर्मी से बचने के लिए अपनी पत्तियों को मोड़कर जीवित रह सकता है।



source :- Down To Earth

- **विश्व बांस दिवस :-** 18 सितंबर को
 - **दुनिया भर में :-** 1500 से अधिक विभिन्न बांस की प्रजातियां हैं
 - बांस घास प्रजाति के अंतर्गत आती है
- विश्व बांस दिवस का इतिहास :-**
- विश्व बांस दिवस की स्थापना :- 2005 में



- ❑ विश्व बांस दिवस की स्थापना विश्व बांस संगठन के प्रयासों से हुई ।
- ❑ विश्व बांस संगठन एक गैर-लाभकारी संगठन है
- ❑ विश्व बांस संगठन की स्थापना सुजैन लुकास और डेविड नाइट्स के द्वारा की गई
- ❑ विश्व बांस संगठन की स्थापना का कारण :-
बांस को एक मूल्यवान और बहुमुखी संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए



- ❑ पहली विश्व बांस कांग्रेस :- विश्व बांस संगठन ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इसका आयोजन साल 2009 में किया

बांस की विशेषताएं :-

- ❑ 1. सूखे के प्रति बहुत सहनशील
- ❑ 2. गर्मी से बचने के लिए अपनी पत्तियों को मोड़कर जीवित रह सकते हैं।
- ❑ 4. तेजी से बढ़ती है और मजबूत, लचीलेपन और पर्यावरण के अनुकूल
- ❑ 5. अविश्वसनीय ताकत व लचीला होने के कारण निर्माण सामग्री, कला और संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए उपयोगी



- ❑ 6.बांस पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक मूल्यवान है।
- ❑ 7.बांस की कोमल टहनियों से स्वादिष्ट एशियाई व्यंजन बनाए जाते हैं।
- ❑ 8.विश्व में 1500 से अधिक विभिन्न बांस के पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।



प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

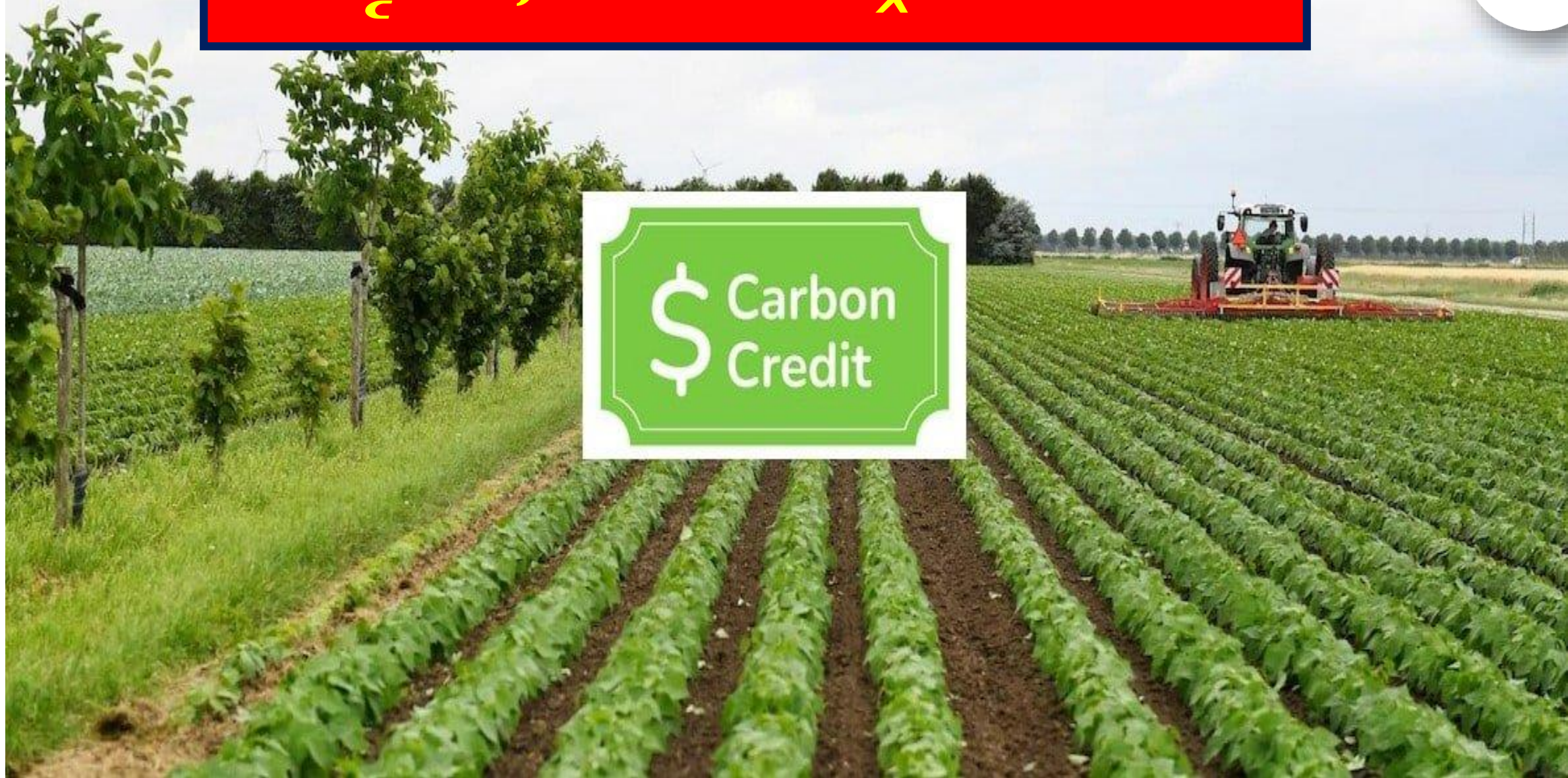
1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 3
- D. 1, 2 और 3



कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र



- ❑ कार्बन ट्रेडिंग के तहत चयनित क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र एक है।
- ❑ सरकार ने दिसंबर 2023 में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र के कार्यान्वयन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया।
- ❑ इस योजना के द्वारा कार्बन ट्रेडिंग के तहत किसानों एवं किसानों से संबंधित संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
- ❑ भारत में कृषि क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक रूपरेखा तैयार की है।



इस रूपरेखा का उद्देश्य :-

- ❑ 1. छोटे और सीमांत किसानों को कार्बन क्रेडिट लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- ❑ 2. किसानों को जब कार्बन बाजार से परिचित कराया जाएगा तो इससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- ❑ 3. कार्बन बाजार से परिचित होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को किसान अधिक तेजी से अपनाने के लिए प्रतीत होंगे।
- ❑ 4. किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।



- ❑ 5. किसान कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे
- ❑ 6. किसान मिट्टी, पानी, जैव-विविधता आदि जैसी प्राकृतिक पूंजी के संदर्भ में अन्य कृषि-पारिस्थितिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।



भारत से बाहर स्थित भारतीय सैन्य बेस



- ❑ मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर बना सैन्य अड्डा ।
- ❑ मॉरीशस हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है,
- ❑ यह देश अफ्रीका के पूर्वी तट पर अवस्थित है।

भूमि:

- ❑ मेडागास्कर से इसकी दूरी लगभग 500 मील/800 किमी पूर्व में।



- ❑ अगालेगा द्वीप, मॉरीशस के द्वीप समूह में प्रमुख द्वीप है जो 580 मील/930 किमी उत्तर की ओर स्थित है।
- ❑ सामरिक दृष्टि से मॉरीशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है।
- ❑ भारत हिंद महासागर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मॉरीशस के साथ में समझौते कर रहा है।
- ❑ भारत और मॉरीशस के मध्य सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अगालेगा द्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।



- ❑ इन समझौता में महत्वपूर्ण है समुद्री सुरक्षा
- ❑ महासागर एक लंबे समय से समुद्री लुटेरों की समस्या से जूझ रहा है साथ में ही भारत को घेरने की चीन की जो नीति है उससे भी भारत अपना बचाव करना चाहता है

भारत और मॉरीशस के इन समझौते से

- ❑ 1.समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- ❑ 2.भारत-मॉरीशस के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी।



- ❑ 3.भारत हिंद महासागर में और अच्छे से निगरानी रख सकेगा
- ❑ मॉरीशस में सेंट जेम्स जेट्टी नामक हवाई पट्टी का उद्घाटन मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ किया
- ❑ साथ ही दोनों ने छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।



भारत और मॉरीशस संबंध :-

- ❑ दोनों देशों के मध्य संबंध स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं
- ❑ जब महात्मा गांधी अक्टूबर 1901 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तो इस दौरान कुछ समय के लिए मॉरीशस में रुके ।
- ❑ मॉरीशस अपना का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है इस दिन ही गांधी जी में दांडी यात्रा (चौबीस दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक) को प्रारंभ किया है।
- ❑ मॉरीशस की कुल आबादी में भारतीयों का लगभग 70 प्रतिशत है।



- प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के (मई 2019 में) शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी शामिल हुए ।

भारत के अन्य देशों में स्थित अन्य मिलिट्री बेस :-

ताजिकिस्तान (Tajikistan)

- राजधानी :- दुशांबे
- ताजिकिस्तान के फरखोर (Farkhor) में भारतीय मिलिट्री का एयर बेस मौजूद है.
- संचालन :- भारतीय वायुसेना द्वारा.



- ❑ यह भारत का पहला ऐसा मिलिट्री बेस है, जो भारत से बाहर स्थापित किया गया .
- ❑ भारतीय वायुसेना ने सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट को यहां तैनात किया हैं.

भूटान (Bhutan)

- ❑ यहां भारत का एक सैन्य बेस एक स्थाई ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मौजूद है.
- ❑ नाम :- भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम (IMTRAT) .



- स्थापना :-1961-62 में की गई थी.
- भूटान में रक्षामंत्री नहीं होते जिस कारण यहां मौजूद कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामलों में सलाह और सहायता प्रदान करता है.

मैडागारकर

- भारतीय मिलिट्री का उत्तरी मैडागारकर में लिसनिंग पोस्ट और एक राडार फैसिलिटी मौजूद है.
- निर्माण :- 2007 में



- ❑ निर्माण क्यों :- 1. हिंद महासागर में जहाजों पर नजर रखी जा सके.
- ❑ 2. समुद्री संचार को सुना जा सके.

ओमान (Oman)

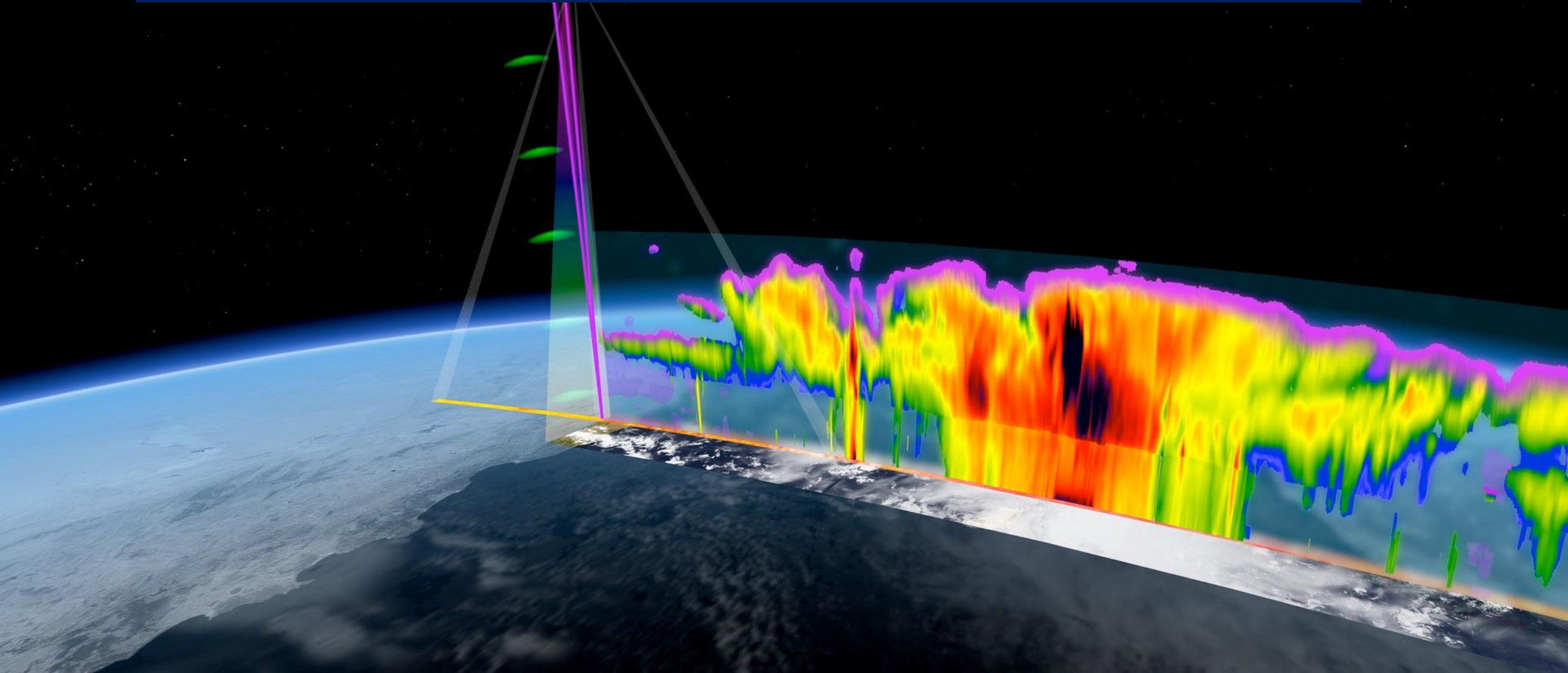
- ❑ यस अल हद में भारतीय मिलिट्री का एक लिसनिंग पोस्ट .
- ❑ साथ ही भारत के पास मस्कट नौसैनिक बेस पर बर्थिंग अधिकार है.



- जिसका अर्थ होता है की इस जगह भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों आदि को जरूरत पड़ने पर ईंधन आदि की सहायता मिल जाएगी .
- Duqm में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का छोटा बेस मौजूद।



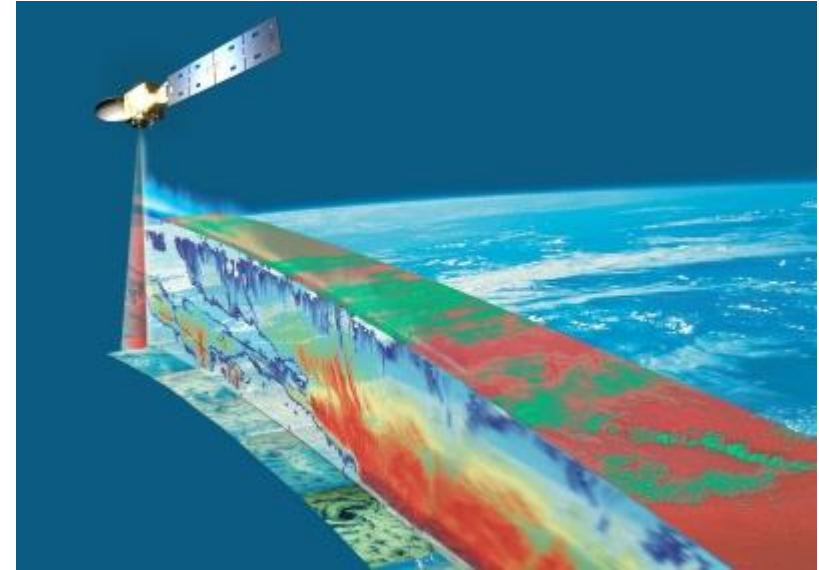
अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर (EarthCARE / अर्थकेयर) मिशन



- ❑ चर्चा में क्यों :- हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) में मिल कर संयुक्त रूप से अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर (EarthCARE / अर्थकेयर) मिशन को लॉन्च किया।
- ❑ अर्थकेयर मिशन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपकरण :- क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार, एटमॉस्फेरिक लिडार, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर (MSI) और ब्रॉडबैंड रेडियोमीटर आदि।
- ❑ मिशन का उद्देश्य :- एरोसोल, बादलों और विकिरण के मध्य जटिल अभिक्रिया का संपूर्ण विश्लेषण करना और उसका विवरण प्रदान करना।



- ❑ क्या होगा विश्लेषण से :- होने वाले जलवायु संकट से पृथ्वी के विकिरण संतुलन में हमें एक नई दृष्टि और समझ प्राप्त होगी।
- ❑ विकिरण संतुलन के बीच बादलों, एरोसोल और पृथ्वी के मध्य क्या संबंध: होता है :-
- ❑ बादल: बादल पृथ्वी के हीट बजट में एरोसोल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ❑ बादल सूर्य से प्राप्त किरणों को परावर्तित करके या पृथ्वी की सतह से होने वाली परावर्तित अवशक्त विकिरणों को वायुमंडल में रोक कर पृथ्वी की सतह को ठंडा या गर्म करने का काम करते हैं।



- ❑ • एरोसोल: ये धूल और प्रदूषक के छोटे छोटे कण होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से हवा में मिले रहते हैं।
- ❑ एरोसॉल भी सौर विकिरण को परावर्तित और अवशोषित करने का कार्य करते हैं
- ❑ एरोसॉल भी पृथ्वी की सतह से होने वाले विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं



विश्व व्यापार संगठन (WTO) और इनपुट सब्सिडी पर आपत्ति



- ❑ चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि इनपुट सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है।
- ❑ यह आपत्ति यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के द्वारा दर्ज की गई है।
- ❑ इसे विश्व व्यापार संगठन की कृषि समिति (Committee on Agriculture) के समक्ष दर्ज किया गया है।
- ❑ यह चिंता भारत द्वारा 2022-23 में की गई कृषि सब्सिडी में 50 परसेंट के वृद्धि को लेकर है।



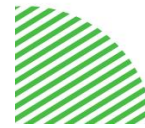
- ❑ भारत द्वारा इस मुद्दे पर अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह इनपुट सब्सिडी सभी किसानों के लिए ना होकर सिर्फ निम्न आय वाले या संसाधन विहीन किसानों के लिए ही उपलब्ध थी जिन्हें कृषि समझौते के तहत छूट प्रदान की गई है

विश्व व्यापार संगठन और कृषि समझौते (Agreement on Agriculture)

- ❑ इस समझौते की अभी पुष्टि मोरक्को के मराकेश में 1994 में की गई थी

AGREEMENT ON AGRICULTURE

World Trade Organization



समझौते के प्रमुख प्रावधान :-

- ❑ बाजार पहुंच: बाजार पहुंच के अंतर्गत प्रशुल्क में कमी टैरिफिकेशन, और बाजार पहुंच के अवसरों को शामिल किया गया है।
- ❑ टैरिफिकेशन के तहत अलग अलग प्रशुल्क को समाप्त करn एक समान प्रशुल्क लागू किया जाएगा।
- ❑ घरेलू पहुंच (Domestic Access): घरेलू पहुंच के अंतर्गत उन सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पर उत्पादन को प्रभावित या व्यापार को विकृत करते हैं।



कृषि के अंतर्गत अलग-अलग प्रकार के सब्सिडी बॉक्स:-

- ❑ इसमें मुख्यतः तीन कृषि बॉक्सों को शामिल किया जाता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स
- ❑ एम्बर बॉक्स: इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की कुछ सीमाएं होती हैं
- ❑ इस सब्सिडी के अंतर्गत कृषि उत्पादन मूल्य की तुलना में न्यूनतम सब्सिडी की अनुमति प्रदान करता है।



- ❑ ब्लू बॉक्स: इस बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत किसानों को भी आवश्यकता होती है की वे उत्पादन सीमित करे अर्थात इसमें उत्पादन का कोटा निर्धारित किया जाता है।
- ❑ ग्रीन बॉक्स: इस बॉक्स के अंतर्गत ऐसी सब्सिडी शामिल की जाती है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है किंतु वे व्यापार को विकृत नहीं करती है या मामूली रूप से विकृत करती है।

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Box Subsidies that do not distort trade, or cause minimal disruption. No limit. | Amber Box Broad range of subsidies. Limited to 5% of agricultural production (10% for developing countries)*. | Blue Box Broad range of subsidies allowed but must be designed to minimise trade distortion No limit. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3



वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी

**वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी
मोदी कैबिनेट में पास हुआ ये प्रस्ताव**



वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब :-

- ❑ एक साथ चुनाव, जिसे लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कहा जाता है, का अर्थ है एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधान सभाओं के चुनाव कराना।
- ❑ क्या पहली बार भारत में लागू हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव
- ❑ आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे
- ❑ लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं।



- ❑ उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई
- ❑ इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई
- ❑ वर्तमान में, ये सभी चुनाव प्रत्येक व्यक्तिगत निर्वाचित निकाय की शर्तों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं



वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी :-

- ❑ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर, 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी।
- ❑ एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी जिसके प्रमुख कोविंद जी थे इसी कारण इस समिति को कोविंद समिति नाम दिया गया



कोविंद समिति में कौन-कौन से सदस्य :-

❑ सदस्य

- ❑ 1. रामनाथ कोविंद, अध्यक्ष (पूर्व राष्ट्रपति)
- ❑ 2. अमित शाह, गृह मंत्री (बीजेपी)
- ❑ 3. हरीश साहू, वरिष्ठ अधिवक्ता
- ❑ 4. अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता
- ❑ 5. गुलाम नबी, डीपीए पार्टी
- ❑ 6. एन के सिंह, 15वें वित्त आयोग पूर्व अध्यक्ष
- ❑ 7. डॉ. सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव
- ❑ 8. संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त.



- इस उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- 21-खंड, 18,626 पेज की विस्तृत रिपोर्ट में 11 अध्याय और अनुबंध शामिल हैं।

कमेटी ने क्या सुझाव दिए?

- 1. विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए।
- 2. पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव और इनके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
- 3. चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाए।



- ❑ 4. देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करने की भी सिफारिश की है।

वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं?

- ❑ 1. बार-बार आचार संहिता लगने की आवश्यकता नहीं :- चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है।
- ❑ 2. राज्य तथा सरकारों को काम करने का अधिक मौका मिलेगा



- ❑ 3.चुनाव खर्च में कटौती: देश में बार-बार चुनाव कराने पर कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है
- ❑ इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये तक हुआ है
- ❑ जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
- ❑ 4.वोट प्रतिशत में वृद्धि: एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में कई वोट डाल सकते हैं, जिससे मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है।



एकल चुनाव उससे संबंधित समस्याएं तथा निराकरण :-

- त्रिशंकु सदन आदि की स्थिति में:
- त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में, सदन की शेष अवधि के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए।

लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करना:

- समिति ने सिफारिश लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से पहले से योजना बनाएगा



- ❑ जनशक्ति, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, ईवीएम की तैनाती के लिए कदम उठाएगा। /वीवीपैट आदि, ताकि सरकार के तीनों स्तरों पर एक साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें।
- ❑ सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।

एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित अन्य देशों में प्रावधान

अमेरिका

- ❑ अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के लिए चुनाव हर चार साल में



- ❑ यह एक निश्चित तारीख पर किए जाते हैं।
- ❑ यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देश में सर्वोच्च कार्यालयों का चुनाव एक साथ कराया जा सके, जिससे एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- ❑ इस प्रक्रिया में संघीय कानून द्वारा निर्धारित चुनाव की तारीखों का पालन शामिल है, जिससे चुनावी गतिविधियों के राष्ट्रव्यापी समन्वय बना रहे।



फ्रांस

- ❑ हर पांच साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली (संसद का निचला सदन) के लिए चुनाव कराए जाते हैं
- ❑ यहां मतदाता एक ही मतदान प्रक्रिया के तहत राज्य के प्रमुख और उनके प्रतिनिधियों दोनों का चुनाव करते हैं



इन देशों में लागू है यह चुनाव व्यवस्था

- दक्षिण अफ्रीका
- स्वीडन
- बेल्जियम
- जर्मनी
- फिलीपींस

- लोकसभा सीटों की संख्या 750 होगी

- वर्तमान में देश में 543 लोकसभा सीट है



- ❑ अगला आम चुनाव साल 2029 में होने है
- ❑ इससे पहले जनगणना होनी है तो परिशीमन भी होगा।
- ❑ तो साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव 750 सीटों पर होगा।
- ❑ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक, एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।



विधानसभा सीटें :-

- ❑ 28 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4130 विधानसभा सीट।
- ❑ सबसे अधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं तो सबसे कम राज्य के हिसाब से सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर देखें तो पुडुचेरी में 30 सीटें हैं।



THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra



+ SUBSCRIBE

